

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,  
सचिव एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 6 अक्टूबर, 2008.

**विषय-** मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- 1022/1989 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य प्रति भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों को उच्चकृत वेतनमान, भत्ते/सुविधाएं प्रदान किया जाना।

महोदय,

अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में मा० शेदूटी आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1022/1989 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य प्रति भारत संघ व अन्य में दिये गये आदेशों के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में मा० उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों को निम्नलिखित सुविधाएं अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) जिला न्यायाधीश के वैयक्तिक सहायक, रीडर ग्रेड-1, प्रोसेस सर्वर का उच्चकृत वेतनमान :-

क्र. सं.	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	उच्चकृत वेतनमान
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वैयक्तिक सहायक	रु० 6500-10500/-	रु० 7450-225-11500/-
2	रीडर ग्रेड- 1	रु० 4500-7000/-	रु० 5500-9000/-
3	प्रोसेस सर्वर (केवल वास्तविक रूप से प्रोसेस सर्वर का कार्य कर रहे कार्मिक के लिये)	रु० 2550-3200/-	रु० 2750-70-3800-75-4400/-

(2) विशेष भत्ता/यात्रा भत्ता - अधीनस्थ न्यायालयों के निम्नलिखित कार्मिकों को उनके सम्मुख अंकित विशेष भत्ता/यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा :-

क्रम सं०	पदनाम	विशेष भत्ता/यात्रा भत्ता
1.	रिकार्ड कक्ष/सम्पत्ति कक्ष में कार्यरत कार्मिक को विशेष भत्ता।	रु० 100/-प्रतिमाह (रुपये एक सौ मात्र)
2.	प्रोसेस सर्वर का कार्य कर रहे तथा अमीन संवर्ग के कार्मिक को नियत यात्रा भत्ता	रु० 200/-प्रतिमाह (रुपये दो सौ मात्र)

3.	विशेष आशुलिपिक / कार्यपालक सहायक, जिसकी नियुक्ति जिला न्यायाधीश द्वारा चयन के उपरान्त की गयी हो, को विशेष भत्ता।	रु0 200/-प्रतिमाह (रुपये दो सौ मात्र)
4.	आशुलिपिक को यात्रा भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ता/विशेष भत्ता:- (i) ऐसे आशुलिपिक जो तहसील / जिला मुख्यालय में कार्यरत हैं (ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में कार्यरत वैयक्तिक सहायक	रु0 100/-प्रतिमाह (रुपये एक सौ मात्र) रु0 200/-प्रतिमाह (रुपये दो सौ मात्र)
5.	समूह 'ग' के कार्मिकों को पोशाक रखरखाव भत्ता	रु0 100/- (रुपये एक सौ मात्र) प्रतिमाह पोशाक रखरखाव भत्ता <b>स्पष्टीकरण-</b> उक्त अनुमन्यता इस शर्त पर प्रदान की जा रही है कि न्यायालय/कार्यालय के कार्मिक शालीन पोशाक में आयेंगे। शालीन पोशाक के बारे में जिला न्यायाधीश के निर्देश मान्य होंगे।

(3) आशुलिपिकों को मानदेय :- आशुलिपिकों को उनके अधिकारी द्वारा उनके संतोषजनक कार्य का प्रमाणपत्र देने पर मानदेय के रूप में प्रतिवर्ष अधिकतम एक माह के वेतन के बराबर की धनराशि प्रदान की जा सकती है।

ऐसे पदधारकों को उक्त के अलावा वर्ष में अन्य मानदेय अन्य इसी प्रकार के अनुमन्य वाले अन्य कार्मिकों के समान नहीं देय होगा।

(4) लिपिक संवर्ग में कार्यरत सभी कार्मिकों को प्रारम्भिक नियुक्ति पर एक वेतन वृद्धि दिया जाना :- न्यायालय में लिपिक संवर्ग में कार्यरत सभी कार्मिकों को प्रारम्भिक मौलिक नियुक्ति के पद के वेतनमान पर ही एक वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।

(5) कामन कैटेगिरी पोस्ट्स (Common Category Posts) के कार्मिकों को उनके वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम पर वेतन वृद्धि :-

अधीनस्थ न्यायालय के निम्नलिखित कार्मिकों को उनके वेतनमान के प्रारम्भिक मौलिक नियुक्ति के पद के वेतनमान पर ही एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी -

- सदर मुंसरिम, वैयक्तिक सहायक,
- केन्द्रीय नाजिर/रिकार्ड कीपर/द्वितीय क्लर्क/हेड कॉपिस्ट/मुंसरिम कम रीडर,
- वाद लिपिक/प्रकीर्ण लिपिक/इजरा लिपिक/अपील लिपिक/सत्र लिपिक/बिल लिपिक/कैशियर/पुस्तकालय लिपिक/आशुलिपिक/रीडर,

10

(iv) सहायक लेखा लिपिक/प्रति लिपिक/ कनिष्ठ लिपिक/वीडर/सहायक रिकार्ड कीपर,

2- उपर्युक्त आदेश दिनांक 1-4-2003 से प्रभावी माने जायेंगे ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1477/XXVII(7)/2008 दिनांक 06 अक्टूबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव,

संख्या: 181(1)/xxxvi(2)/2008-120-एक(1)/04 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 3- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून ।
- 4- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
- 5- समस्त कुटुम्ब न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 7- वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन ।
- 8- एन०आई०सी०/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।